[श्री वृद्धिचन्द्र जैन]

कारण उसी भयंकर गरीबी और कर्ज का सामना करना पड़ रहा है ।

विद्युत उत्पादन की कमी का मुख्य कारण कोटा अणु बिजली घर की दोनों इकाइयों का बार बार खराब होना और साल में अधिकांश महीनों में बन्द रहना है और इस समय भी दोनों इकाइयां बन्द हैं। मध्य प्रदेश सरकार का सतपुड़ा में राजस्थान सरकार को उसका हिसाब नहीं देना है और गांधी सागर में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भराव क्षेत्र में कई बांधों का बनाना और कम वर्षा का होना भी है।

राज्य को 180 से 220 लाख यूनेट प्रति दिन बिजली की आवश्यकता है जबकि केन्द्र सरकार द्वारा बदरपुर से बिजली की सहायता देने के उपरान्त भी 90 लाख यूनिट प्रति दिन बिजली मिल रही है।

अतः केन्द्र सरकार से निवेदन है कि वह कृषि एवं उद्योगों के विकास और विस्तार के लिए सिंगरौली से 30 लाख यूनिट प्रति दिन और गुजरात सरकार, जोकि विद्युत की दृष्टि में अच्छी स्थिति में है, 30 लाख यूनेट प्रति दिन लोन के रूप में दिलाया जाय ताकि राजस्थान जोकि चार वर्षों से भयंकर अकाल से प्रभावित है और जिसपर 340 करोड़ रुपये की ओवरड्राफ्ट है और जो बड़े उद्योग संकट से गुजर रहा है, इस संकटमय स्थिति को पार कर सके।

(iv) CENTRAL ASSISTANCE FOR CONSTRUCTION OF PALANA THERMAL POWER PROJECT IN RAJASTHAN.

श्री अशोक गहलोत (जोधपुर): उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो दशक से प्रस्तावित राजस्थान के पलाना ताप बिजली घर के निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं होने से पूरे प्रदेश में चिन्ता व्याप्त है क्योंकि पूरे प्रदेश का किसान, उद्यमी व आम उपभोक्ता स्थायी रूप से भयंकर विद्युत संकट से पीड़ित हो गया है । राजस्थान परमाणु बिजली घर की दोनों यूनिटें स्थायी रूप से बन्द हो जाने से लम्बे समय तक यह भीषण विद्युत संकट बने रहने की सम्भावना है ।

पलाना (बीकानेर) में लिग्नाइट कोयले के विपुल भंडार हैं, उसमें कम से कम 50 वर्ष तक कोयला निकाला जा सकेगा । यहां के कोयले को जर्मन के विशेषज्ञों व जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया ने भी अनुकूल पाया है एवं ऐसी भी जानकारी मिली है कि कोयले की तकनीकी जांच हेतु इसे जर्मनी भेजा गया एवं जर्मनी से प्राप्त रिपोर्ट में भी उसे अनुकूल माना है।

13.00 hrs.

मान्यवर, पलाना थर्मल पावर प्रोजेक्ट राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है क्योंकि इसी के माध्यम से ही पूरे प्रदेश के बिजली संकट को काफी हद तक दूर करने में स्थायी रूप से सहायता मिल सकेगी। यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि सैन्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी आथोरिटी आफ इन्डिया तथा योजना आयोग ने इस परियोजना को आर्थिक व तकनीकी रूप से लगभग एक वर्ष से भी अधिक समय हुआ स्वीकृति दे दी है। लगभग 107 करोड़ रुपये की इस योजना को भारत पूर्वी जर्मनी संयुक्त आयोग द्वारा पूरा कराने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है ।

राजस्थान सरकार ने पलाना थर्मल पावर प्रोजेक्ट पर कार्य प्रारम्भ करने हेतु एक चीफ इंजीनियर, अतिरिक्त चीफ इंजीनियर, सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर तथा कई अन्य पदों पर नियुक्तियां भी कर दी एवं प्रशासन द्वारा पलाना ग्राम पंचायत में किसी प्रकार के नये निर्माण पर रोक लगा दी गई है । वहां के निवासियों की संम्पत्ति व भूमि का मूल्यांकन कर जिला प्रशासन ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट भी प्रेषित कर दी । संपत्ति व भूमि हस्तातरण तथा मुआवजे की शर्तें आदि तय करने के लिए सारा मामला राज्य सरकार के विचाराधीन प्रस्तुत कर दिया गया परन्तु इस स्तर पर पहुंचने के बाद इस परियोजना का कार्य अज्ञात कारणों से या तो आगे रोक दिया गया है अथवा पूरा ही बंद कर दिया गया है। इससे पूरे क्षेत्र में चिंता व्याप्त हो गई है क्योंकि इसी पलाना थर्मल पावर प्रोजेक्ट से ही लोगों को भविष्य के लिए आशाएं हैं वरना वर्तमान हालात में

तो राजस्थान के कृषि व उद्योगों को ऐसी क्षति हो रही है कि उसे अविलम्ब अगर पड़ौसी राज्यों से विद्युत दिलाने में केन्द्र ने मदद नहीं की तो आने वाले कई वर्षों तक कृषि व उद्योग चौपट हो जायेगें । कई उद्योग राजस्थान जैसे पिछड़े प्रदेश से पलायन कर जायेगें, नये उद्यमी साहस नहीं करेंगे व प्रदेश और भी अधिक पिछड़ता जायेगा जिस को दुबारा साधारण स्थिति में आने में कई वर्ष लग जायेगें क्योंकि कृषि उत्पादन व औद्योगिक उत्पादन दोनों ही राजस्थान में इस राष्ट्रीय उत्पादकता वर्ष में सब से कम कर पायेगें ।

इस लिए मेरा ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन है कि वे पलाना थर्मल पावर प्रोजक्ट हेतु राज्य सरकार को सभी तरह की सहायता दे कर इसे शीघ्र पूरा करवाने हेतु आवश्यक कदम उठायें ।

(v) SETTING UP OF A T.V. CENTRE AT KODAIKANAL IN TAMIL NADU.

SHRI CUMBUM N. NATARAJAN (Periyakulam): Under rule 377, I am making the following statement.

Kodaikanal in Tamilnadu, an acknowledged Hill Resort, has been chosen for Television tower and station in the Sixth Five Year Plan. The other places included in the Sixth Five Year Plan are Asansol, Cuttack, Panaji, Kasauli, Murshidabad Vijayavada and Varanasi. When this Television Tower and Station became a reality, the people living in Madurai, Coimbatore and Ramanathapuram districts and those in Tirunelveli, Tiruchirapalli, Salem and Nilgiris districts will get the benefit. Unfortunately, so far necessary steps have not been taken to start the work. Even the land acquisition proceedings have been not taken up so far.

Meanwhile, there has been a spurt in the sale of TV sets during the past 3 months in Tirunelveli and other Southern districts of Tamilnadu. The reason for this is that they are able to get the transmission of TV Broadcasts from Sri Lanka. Many Tamil Films and interesting cartoons are being shown by Sri Lanka T.V. which has been named Roopavahini. This has been established with the help of Japan and the U.S.A. These two countries have given very powerful machinery which can transmit T.V. films across the seas.

Though the Expenditure Finance Committee has sanctioned Kodaikanal T.V. Tower and Station and though indents for supply and erection of tower have been placed on 16-11-1980 on the Director-General of Disposal and Supplies, yet this project has not come about. The incordinate delay is leading to undue influence among the people from Sri Lanka T.V. This can be stopped only when Kodaikanal T.V. Tower and Station comes about. Necessary steps are to be taken immediately in this matter.

(vi) NEED TO CONTINUE PUBLIC HEALTH CARE SCHEME IN BIHAR.

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, 3 अक्तूबर, 1977 से देश भर में जन स्वास्थय रक्षक योजना कार्य क्रम लागू किया गया था । इस के अन्दर एक हजार ग्रामीण जनता पर एक प्रशिक्षित जन-स्वास्थ्य रक्षक को स्वंय सेवक के रूप में बहाल किया गया और उन्हें वजीफा के रूप में 50 रुपये प्रतिमाह और 50 रुपये की दवा बिना मूल्य वितरण हेतु दी जाती थी। इससे सुदूर बसे ग्रामीणों की प्राथमिक चिकित्सा परिवार नियोजन कार्यक्रम आदि लाभदायक कार्य किये जाते थे ।

बिहार में भी यह योजना प्रथम चरण में 82 प्रखंडों में लागू किया गया है, जिसमें करीब साढ़े सात हजार प्रशिक्षित जन-स्वास्थ्य रक्षक को कार्यरत कराया गया है। 1 सितम्बर, 80 से राज्य सरकार ने वित्तीय संकट कह कर इसे बंद कर दिया। उस समय केन्द्रीय सरकार 50 प्रतिशत खर्च देती थी। अब केन्द्रीय सरकार ने 1 दिसम्बर 1981 से शत प्रतिशत व्यय वहन करना स्वीकार कर लिया है । जिसकी सूचना राज्य सरकारों को दी जा चुकी है । उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आदि प्रान्तों में जहां यह पहले ही लागू था, इसे लागू रखा गया